

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक 06 जून, 2013

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनेतर पक्ष की "वनों की सुरक्षा" योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0- 284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-नि- 2043/3-2(आयोजनेतर-वनों की सुरक्षा), दिनांक 23 अप्रैल, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेतर पक्ष की "वनों की सुरक्षा" योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये प्राविधियानित आय-व्ययक के सापेक्ष ₹ 4,00,000/- (रु चार लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्धरण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/व्यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनाएँ एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (जट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिग्राहित (प्रैक्चरोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
3. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यवसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदो के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो के अन्तर्गत ही रहेगी।
4. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माव्यग से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.

5. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फौल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
6. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी०एम० प्रपत्र पर प्रत्यक्ष माह प्रशासनिक विभाग एवं वित विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
7. निर्धारित बी०एम० प्रपत्र पर व्यय विवरण नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
8. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति में अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष व्यान रखा जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आंवटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-०६/X-२-२०१०-१२(११)/२००९ दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनेजल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
11. व्यय में मितव्ययता निरान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेतर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
12. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
13. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1306270251 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण 0300 वनों की सुरक्षा के निम्नलिखित सूची में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जाएगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कार्पी भी संलग्न की जा है।

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र० सं०	लेखा शीर्षक / योजना मानक भद्र का नाम	आय-व्ययक 2013-14	शासन से पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	आय-व्ययक के सापेक्ष अवशेष बजट	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
	2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01- वानिकी 101-वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण 03-00-वनों की सुरक्षा 28-मशीन साज सज्जा/उपकरण एवं संयत्र 29-अनुरक्षण				
	योग	600	0	600	400

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ चार लाख मात्र)

3- ये आदेश वित्त विभाग के अंशां संख्या 12(NP)/XXVII(4)/2013 दिनांक 31 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

मवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संख्या- ८५१ (1)/X-2-2013, तददिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्ये, देहरादून.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. प्रमारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,
(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2013/2014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - S1306270251

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई ई - S1306270251

आवंटन पत्र दिनांक - 05-Jun-2013

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक	2406 - वानिकी तथा बन्य जीवन	01 - वानिकी
	101 - वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण	03 - बनो की सुरक्षा
	00 - बनो की सुरक्षा	

Non Plan Voted

मानक भद्र का नाम	पूर्त में जारी	वर्तमान में जारी	योग
26 - बर्बादी और सज्जा /उपकरण और	0	100000	100000
29 - अनरक्षण	0	300000	300000
	0	400000	400000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 400000